बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 205

प्रमाण आधारित नीति का सम्मान

पांच वर्ष में दूसरी बार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने विकास संबंधी अर्थशास्त्र के शोधार्थियों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है। सन 2015 में एंगस डीटन के बाद इस वर्ष अभिजित बनर्जी, एस्टर डफ्लो और माइकल क्रेमर को यह पुरस्कार दिया गया। हालांकि इन सभी ने गरीबी, असमानता और जनकल्याण जैसे समान विषयों पर शोध किए हैं लेकिन इस वर्ष पुरस्कृत तीनों अर्थशास्त्री प्रोफेसर डीटन से एकदम अलग रुख रखते हैं। डीटन को यह पुरस्कार उस काम के लिए मिला जिसमें उन्होंने व्यापक डेटा सेट का उपयोग किया और उपयुक्त लेकिन बहसतलब अनुमान पेश किए। दूसरी ओर इस वर्ष के विजेताओं ने उक्त प्रश्नों को छोटे आकार में कर दिया है जिनके बारे में सुनिश्चित होकर बात कही जा सकती है। आशा यह है कि अधिक श्रमसाध्य तरीके से अर्जित परिणाम विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को प्रमाण आधारित नीति बनाने में मदद करेंगे।

यहां भी बुनियादी रुख करीब-करीब वैसा ही है जैसा कि चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए परीक्षण यानी बेतरतीब समूहों को जांची जा रही नीति के समक्ष उपचारार्थ पेश किया जाता है जबकि दूसरे समूह के साथ ऐसा नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें नीतिगत प्रायोगिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीतियों का प्रयोग करने के पश्चात दोनों समूहों पर प्रभाव की तुलना की जाती है। अगर प्रायोगिक समूह और नियंत्रित समूह के बीच सांख्यिकीय रूप से स्पष्ट और वांछित अंतर नजर आता है तो नीतियों के प्रभाव को लेकर ठोस नतीजे निकाले जा सकते हैं। चूंकि दोनों समूहों का गठन बेतरतीब था इसलिए नतीजों में अंतर के लिए कोई अन्य कारक उत्तरदायी नहीं हो सकता। विकासात्मक अर्थशास्त्र जैसे वैचारिक और बहसतलब क्षेत्र में यह रुख अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में तो नीतियों पर इसलिए भी हमला हो सकता है कि वह किसी खास समूह के निहित लाभ को बढ़ावा दे रही है या वास्तविक श्रेष्ठता न होने पर भी उन नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समय के साथ विकास अर्थशास्त्र में ऐसे परीक्षणों का दबदबा बढ़ रहा है। इससे प्रोफेसर डीटन जैसे व्यापक संदर्भों पर काम करने वाले अर्थशास्त्रियों और सिद्धांतकारों का खीझना लाजिमी है।

इसका भारत जैसे देश पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। हाल के कुछ प्रभावशाली नीतिगत नवाचार, उदाहरण के लिए आधार से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तक में इस तरह के अध्ययन शामिल किए गए हैं। यह नोबेल पुरस्कार भी तीनों विजेताओं के तथा इस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों तथा संस्थानों के सहयोग के बिन मिलना संभव नहीं होता। ऐसे संस्थानों में भारत सरकार की केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां भी शामिल हैं। यह देखना आसान है कि आखिर क्यों ऐसा विश्लेषण भारतीय संदर्भों में मायने रखता है। अफसरशाहों के पास क्रियान्वयन के लिए जितना समय, ऊर्जा या संसाधन होते हैं, उससे कहीं अधिक प्रस्ताव होते हैं। जिन प्रस्तावों के साथ सफलता का सुनिश्चित प्रमाण संलग्न हो उनको प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। परंतु यह भी सही है कि प्रमाण आधारित नीति निर्माण को उतना विस्तार नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। वास्तव में इस रुख की एक आलोचना यह है कि सरकार इनको व्यापक तौर पर लागू करने की इच्छुक नहीं रही। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र में ऐसे प्रयोग से उभरे केवल एक या दो हस्तक्षेप अपनाए गए हैं। आशा की जानी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद नीतिगत क्षेत्र के लोग जागेंगे और अकादमिक जगत से सामने आ रहे निष्कर्षों पर ध्यान देंगे।

विनय सिन्हा

कॉर्पोरेट कर कटौती और सकारात्मक प्रभाव

घटी हुई दरें तभी प्रभावी असर छोड़ सकती हैं जब उनके साथ नीतिगत सुधारों को भी अंजाम दिया जाए। ऐसा होने पर ही मध्यम अवधि में वृद्धि में सुधार देखने को मिलेगा। विस्तार से बता रहे हैं शंकर आचार्य

गत 20 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में बड़ी कंपनियों पर लगने वाले कर ढांचे में अहम सुधार की घोषणा की। कंपनी आयकर की बुनियादी दर को 30 प्रतिशत (उपकर और अधिभार सहित 35 फीसदी) से घटाकर 22 फीसदी (उपकर और अधिभार सहित 25 फीसदी) कर दिया गया। इसके अलावा 1 अक्टूबर, 2019 के बाद स्थापित होने वाली नई विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 फीसदी (उपकर और अधिभार सहित 17 फीसदी) कर दर रखी गई। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को उपकर और अधिभार समेत घटाकर 17 फीसदी कर दिया गया। इन घटी कर दरों का लाभ लेने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन और रियायत छोड़ने को कहा गया। शेयर बाजार सूचकांकों में उछाल आई और उद्योग जगत भी उत्साहित नजर आया। विश्लेषकों और टीकाकारों की टिप्पणी अवश्य मिलीजुली रही। वे सतर्कतापूर्वक स्वागत कर रहे थे लेकिन साथ ही राजकोषीय तनाव के दौर में कंपनियों को दी जा रही राहत को लेकर चिंतित भी थे। संतुलित विचार कायम करने के लिए उचित यही होगा कि कंपनी कर नीतियों में हुए इस बड़े बदलाव के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की जाए।

पहला, कर कटौती अल्पावधि में राजकोषीय प्रोत्साहन देती है। सरकार का अनुमान है कि इससे 1.45 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी के 0.7 फीसदी के बराबर की क्षति होगी। परंतु तमाम विश्लेषकों (बिज़नेस स्टैंडर्ड में ए के भट्टाचार्य और हिंदू बिजनेस लाइन में सी रंगराजन तथा डी के श्रीवास्तव) के मुताबिक यह अनुमान अतिरंजित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इसमें उस महत्त्वपूर्ण राजस्व लाभ को भी शामिल किया गया हो जो कम कर दर से लाभान्वित होने के लिए दी गई रियायतों के कारण हासिल होना हो। जबकि रियायतों को त्यागना कम कर दर के लाभ लेने के लिए आवश्यक है।

बजट अनुमान के मुताबिक 2018-19 में कॉर्पोरेट कर से जुड़ी रियायत और प्रोत्साहन पर 1.08 लाख करोड़ रुपये गए। मोटे तौर पर ऐसा अधिमूल्यन में तेजी और निर्यात संबंधी लाभ के कारण हुआ। 2019-20 में इसके अच्छे खासे हिस्से को त्यागकर घटी कर दर का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे में कर कटौती के कारण होने वाली राजस्व हानि जीडीपी के 0.4 से 0.5 फीसदी रह जाएगी।

दूसरा, इस प्रोत्साहन के साथ अतिरिक्त सरकारी उधारी की सहायता से उच्च राजकोषीय घाटे की भरपाई की जाएगी। इससे मध्यम और लंबी अवधि में ब्याज दरों में इजाफा होगा जो निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके आधार पर घोषणा के बाद मानक प्रतिफल में बढ़ोतरी की बात को समझा जा सकता है।

10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड में 20 आधार अंक की बढ़ोतरी की बात कही गई है। यानी निवेश को कुछ सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा तथा बॉन्ड बाजार के घटनाक्रम से उपजे अन्य व्यय को संतुलित किया जा सकेगा।

तीसरा, कंपनी कर में यह अहम कटौती कॉर्पोरेट निवेश पर सकारात्मक असर डाल सकती है। कर दर को 35 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करना कर पश्चात प्रतिफल दर को बढ़ा सकता है। परंतु कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। प्रोत्साहन और रियायत के कारण कर कटौती का असर अलग-अलग कंपनियों पर अलग-अलग होगा। हो सकता है कई कंपनियां रियायतों को ही चुनें। कई ऐसी कंपनियां जिनको कर कटौती से लाभ हो रहा है उनकी बैलेंसशीट नकदीकृत हो सकती है। ऐसे में शायद वे अल्पावधि में अपने पूंजीगत व्यय की योजनाओं में तब्दीली न करें। कर बचत के अन्य लाभार्थी इस लाभ का इस्तेमाल नकदी की तंगी दूर करने और तनावग्रस्त बैलेंस शीट में सुधार करने में करेंगे। क्रेडिट सुइस ने 30 सितंबर को प्रभाव विश्लेषण जारी किया जिसमें अनुमान जताया गया है कि अल्पावधि की कर कटौती से होने वाले लाभ का 90 फीसदी हिस्सा या तो अतिरिक्त मुनाफे के रूप में रहेगा या नकदीकरण के काम आएगा। यकीनन आगे चलकर अन्य आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रम के चलते कॉर्पोरेट निवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी अपेक्षा है।

नई कंपनियों के लिए कर दर को 35 फीसदी से घटाकर 17 फीसदी करने से आने वाले समय में इस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों तरह का निवेश बढ़ना चाहिए। परंतु कर कटौती से जुटने वाले निवेश की राशि कुछ अन्य नीतिगत बातों पर भी निर्भर करेगी जिनमें भूमि और श्रम नीतियां, वित्तीय और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की स्थिति, कारोबारी सुगमता, अन्य कर नीतियां, राजकोषीय विवेक तथा विनिमय दर प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं। अगर इन मामलों में सकारात्मक कदम उठते हैं तो निवेश पर सकारात्मक असर होगा। लेकिन इसका उलटा भी हो सकता है।

चौथी बात, कर कटौती निजी निपवेश और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए स्पष्ट संकेत लिए हुए है। इसका कंपनियों की निवेश योजनाओं पर सकारात्मक असर होना चाहिए। जाहिर है इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल यह सकारात्मक असर भी व्यापक नीतिगत कारकों का मोहताज होगा।

पांचवां, कुछ लोगों का कहना है कि 20 सितंबर के कदमों के बाद शेयर बाजार में आई उछाल शेयर बाजार के मूल्यांकन और इस प्रकार संपत्ति पर पर सकारात्मक असर डालेगी और इससे खपत और निवेश में व्यय बढ़ेगा।

मैं इसे लेकर दो वजह से शंकालु हूं। पहली बात, देश में परिसंपत्ति प्रभाव का विश्वसनीय मात्रात्मक आकलन अप्राप्यता के लिए जाना जाता है। दूसरा, शेयर कीमतों में इन दिनों जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में इसका सटीक उदाहरण देखने को मिला।

मुझे इस बात को लेकर अचरज ही है कि कर कटौती से कितना विदेशी पूंजी निवेश आएगा और किन क्षेत्रों में आएगा। मेरी चिंता यह है कि यदि गैर कारोबारी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश आया तो क्या होगा। इससे पहले से अधिमूल्यित विनिमय दर और बढ़ेगी। विनिमय दर अधिमूल्यन, आयात सब्सिडी और निर्यात पर कर का कुल मिलाकर निवेश और आयात प्रतिस्पर्धा तथा औद्योगिक निर्यात वृद्धि पर नकारात्मक असर हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें विनिमय दर का बेहतर प्रबंधन करना होगा।

यानी संक्षेप में और मध्यम अवधि में कर कटौती का निवेश और वृद्धि पर क्या असर हो सकता है? यह कह पाना मुश्किल है। मेरी अपनी समझ कहती है कि अल्पावधि में इसका मामूली असर होगा और मध्यम अवधि में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर सार्थक सुधार अपनाए गए तो यह सकारात्मकता कई गुना बढ़ सकती है।

थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर दूर कर सकते हैं ऊर्जा का गतिरोध

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

सौर ऊर्जा हरित आंदोलन के आधारस्तंभों में से एक है। जहां सौर उपकरण विनिर्माता पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वहीं इसने जीवाश्म ईंधनों की जरूरत कम कर दी है। लेकिन सौर ऊर्जा की एक बड़ी खामी भी है। उसमें निरंतरता की कमी है। रात के समय पड़ने वाले गतिरोध के अलावा ध्रुवों के नजदीक ऐसे इलाके भी हैं जहां कई महीनों तक सूर्य दिखता ही नहीं है। इसका मतलब है कि वहां अन्य ऊर्जा स्रोतों की भी जरूरत है।

ऐसा ही एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत 200 वर्षों से प्रचलित परिघटना का दोहन कर सकती है। यह स्रोत थर्मोइलेक्ट्रिसिटी है यानी तापमान भिन्नता से पैदा होने वाली बिजली। कई तरह के प्रायोगिक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों का प्रयोगशाला एवं वास्तविक हालात में परीक्षण किया जा रहा है। इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने 1790 में पाया था कि ताप भिन्नता होने पर विद्युत-धारा एक सर्किट के जरिये प्रवाहित होती है। इसके उलट अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ताप भिन्नता की स्थिति पैदा होती है। थॉमस सीबेक और ज्यां-चार्ल्स पेटियर ने 1820 के दशक में इस धारणा को और परिष्कृत किया। लॉर्ड केल्विन ने भी 1850 के दशक में इस पर शोध कर प्रभावों को परिभाषित करने वाले अहम समीकरणों के बारे में बताया। किसी घर की भीतरी एवं बाहरी दीवारों के बीच भी प्राकृतिक रूप से ताप विभेद हो सकती है। इन प्राकृतिक ताप भिन्नताओं का चतुराई से प्रयोग कर थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों का निर्माण किया जा सकता है। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के वेई ली की अगुआई वाली टीम ने यह कहा है कि उन्होंने किस तरह एक ऐसा जनरेटर बनाया जो एलईडी बल्बों को रोशन करने लायक बिजली पैदा कर लेता है। इस जनरेटर में दो एल्युमीनियम प्लेटें लगी हैं जिनमें से निचली प्लेट तत्त्वों के संपर्क में रहने के नाते आसपास की हवा के तापमान से प्रभावित होती है। वहीं ऊपरी प्लेट एक पारदर्शी आवरण में सीलबंद होती है जिससे होकर सौर विकिरण गुजरता है। ऊपरी प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है ताकि वह हवा के संपर्क में आकर गर्म या ठंडी न हो जाए। रात में यह सीलबंद प्लेट तेजी से ठंडी हो जाती है क्योंकि यह उष्मा को इन्फ्रारेड में बिखेर देती है। इस दौरान निचली प्लेट आसपास की हवा के चलते गर्म होती रहती है।

गत दिसंबर में कैलिफोर्निया में किए गए इस उपकरण के परीक्षण के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की भिन्नता पाई गई थी। इतनी भिन्नता प्रति वर्ग मीटर प्लेट में 25 मिलीवाट बिजली पैदा करने के लिए काफी है। शोध टीम का मानना है कि बेहतर डिजाइन और अधिक चतुर उपयोग से पैदा होने वाली बिजली की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। करीब 500 मिलीवाट प्रति वर्ग मीटर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा जा सकता है।

वह बिजली भी सौर पैनलों से पैदा होने वाली बिजली से काफी कम होगी जो प्रति वर्ग मीटर इलाके में 100 वाट से भी अधिक बिजली पैदा करता है। हालांकि जगह के अभाव को कोई अवरोध न मानें तो ऐसे 'नाइट पैनल' सौर ऊर्जा से वंचित इलाकों में लगाए जा सकते हैं। यह शोधपत्र कहता है, रात में बिजली पैदा करने की क्षमता हासिल करने का मतलब यह है कि दूरदराज के मौसमी स्टेशनों में रोशनी करने एवं कम खपत वाले सेंसरों जैसे कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर इस डिजाइन को जमीन पर उतारा जा सकता है तो रात के समय की प्राकृतिक शीतलता का इस्तेमाल सलीके से हो सकेगा।

हालांकि थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों को क्रियाशील बनाने और उन्हें वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई इंजीनियरिंग चुनौतियों से पार पाना है। पहला, जनरेटर में इस्तेमाल सामग्री उच्च विद्युत चालक हो और आदर्श रूप में तापीय चालकता निम्न हो। उच्च विद्युत चालकता होने से धारा का प्रवाह आसान हो जाता है जबकि निम्न तापीय चालकता यह सुनिश्चित करती है कि ताप विभेद बहुत जल्द सामान्य न हो जाए। ऐसी अधिकांश सामग्री बहुत महंगी होती है। फिर भी स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के डिजाइन में एल्युमीनियम का इस्तेमाल कर समस्या दूर करने की कोशिश की गई है। नैनो-तकनीक भी विद्युत चालकता पर डाले बगैर सामान की तापीय चालकता कम करने का किफायती रास्ता बताने का वादा करती है। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ खास लाभ भी हैं। उसका कोई हिस्सा चलायमान नहीं होने से रखरखाव की भी कम जरूरत है। इसके अलावा उन्हें ईंधन या लुब्रिकेंट की भी जरूरत नहीं है। वे अवशिष्ट ऊष्मा को बिजली में तब्दील कर सकते हैं जो कारों एवं कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बड़ी बात है।

नासा एवं अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इनका खास तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये उपकरण अंतरिक्ष में भी काफी कारगर हैं जहां सीधी रोशनी और अंधेरे में रखी वस्तुओं के तापमान में बड़ा फर्क होता है।

थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों के लिए वैश्विक बाजार वर्ष 2015 में महज 32 करोड़ डॉलर ही था लेकिन इसके 15 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ने का दावा किया जा रहा है। इस वृद्धि के पीछे एक बड़ी वजह वाहन निर्माताओं से मांग में आई तेजी है। ऑटो कंपनियां इंजन से निकलने वाली गर्मी को बिजली में तब्दील करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगी हैं। शरीर में पहने जा सकने वाले उपकरण भी मददगार हो सकते हैं। यह संभव है कि शरीर की उष्मा का इस्तेमाल छोटे उपकरणों को चलाने में किया जाए। सोनी ने जेब के आकार के एयर कंडिशनर 'रेयॉन पॉकेट' को प्रदर्शित किया है। क्राउड-सोर्सिंग से तैयार इस जेबी एयर कंडिशनर को अगले साल उतारने की तैयारी है। यह 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घटा और फिर 8 डिग्री तक बढ़ा सकता है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की वजह से कम ऊर्जा वाले थर्मोइलेक्ट्रिक को रफ्तार मिल सकती है। आईओटी में अमूमन कम ऊर्जा वाले सेंसरों की जरूरत होती है और इसमें रखरखाव की भी कम जरूरत होती है। इसका भी बड़ा बाजार हो सकता है।

कानाफूसी

परिवार का साथ

रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के बीच के झगड़े में परिवार छोटे भाई शिविंदर के पक्ष में खड़ा नजर आता है। पिछले दिनों जब आदेश की प्रति लेने के अवसर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर परिजनों और शिविंदर के बीच का लगाव साफ झलक रहा था। शिविंदर को पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाए जाने के पहले आधे घंटे तक परिजनों ने उनसे खूब बातचीत की। इस अवधि में मालविंदर ज्यादातर वक्त अकेले बैठे रहे। उनके साथ केवल उनके वकील और कुछ अन्य लोग नजर आए। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि परिवार अपना मन बना चुका है कि इस लड़ाई में किसका साथ देना है। शुक्रवार को निचली अदालत ने दोनों भाइयों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की चार दिन की हिरासत में भेज दिया था।

राज बब्बर का खत

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राज बब्बर ने राज्य इकाई को विदा कहते हुए पार्टी के नए अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू को एक पत्र लिखा। बब्बर ने कहा कि अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान तमाम गंभीर प्रयासों के बावजूद वह अच्छे नतीजे दे पाने में कामयाब नहीं रहे। बब्बर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी टिप्पणी की। उन्होंने पत्र में लिखा कि कई बार उनके निर्णय या उनके वरिष्ठ नेताओं के निर्णय भी पार्टी के भीतर अपेक्षित समर्थन पाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी में युवा नेताओं को बढ़ावा देने और वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ लेने की कोशिश की लेकिन यह पार्टी की राज्य इकाई के कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लगा।

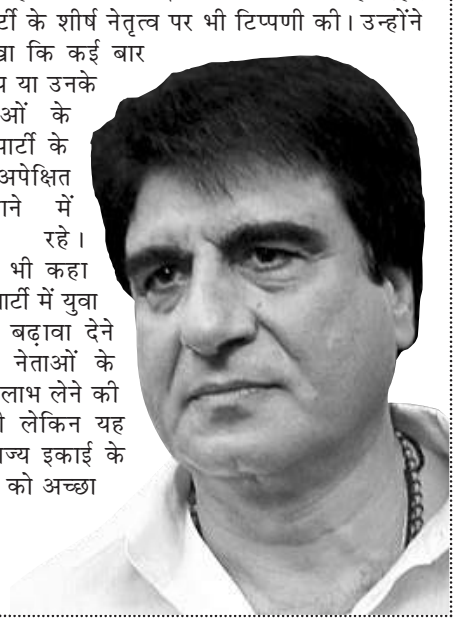

आपका पक्ष

सुस्ती खत्म करना नामुमकिन नहीं

आर्थिक समीक्षा 2018-19 में निवेश को देश की तरक्की के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बताया गया था और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। इससे नई नौकरियां पैदा होती हैं, नई तकनीक आती है साथ ही उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आज के हालात को देखें तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हालांकि सरकार निवेशकों को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकार कॉरपोरेट कर में कटौती कर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह उद्योग जगत के साथ खड़ी है। इससे उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान निवेशकों को भारत में निवेश करने का निमंत्रण दिए। लेकिन कितना निवेश आएगा यह कहना मुश्किल है। आर्थिक सुस्ती से निजात पाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका झुकाव आपूर्ति बढ़ाने की तरफ ज्यादा है जबकि आर्थिक

सुस्ती का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मांग बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को जमीनी स्तर पर ऋण की उपलब्धता की उचित और सार्थक प्रयास जारी रखने होंगे। ऋण मेले में ऋण लेनेवालों की भागीदारी बहुत उत्साहजनक नहीं रही। बैंक आसान शर्तों पर ऋण देने की बात

आर्थिक सुस्ती खत्म करने के लिए सरकार को मांग बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा

तो कर रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जरूरतमंद व्यापारियों को आसान शर्तों पर उचित अनुपात में ऋण मिले इसपर काम करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एक अच्छा प्रयास है लेकिन जमीनी स्तर पर ठीक से अमल नहीं हो पाया है। सरकार को सार्वजनिक निवेश बढ़ाना होगा। इससे ग्रामीण जनता को रोजगार मिलेगा। उनकी आमदनी बढ़ेगी और मांग में बढ़ोतरी होगी। मनरेगा, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तार जैसी योजनाओं से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना उचित कदम हो सकता है। अगर सरकार ने बीएसएनएल को 10 साल पहले बेच दिया होता तो इसकी कीमत एक लाख करोड़ रुपये होती। आज इसे दोबारा खड़ा करने के लिए सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।

राजीव सिंह, हैदराबाद

रोजगार उन्मुख शिक्षा व्यवस्था जरूरी

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7 फीसदी है और पिछले दो वर्षों से बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। सरकार बेरोजगारी दूर करने में अब तक असफल रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों में रिक्त पद पर नियुक्ति नगण्य रही है जबकि निजी कंपनियों में अवसर होने के बावजूद कुशल उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अशिक्षित लोगों के मुकाबले शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की दर अधिक है। देश में रोजगार उन्मुख शिक्षा व्यवस्था लागू करना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की कमियों को दूर करके उसे ठीक से क्रियान्वयन करना चाहिए। बेरोजगारी समस्या से निपटने एवं आर्थिक विषमता कम करने के लिए सरकार को शिक्षा तंत्र की उन्नति के लिए आवश्यक उपाय खोजने चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।